सटीक जनगणना विकास योजनाओं का महत्वपूर्ण आधार है- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने जनगणना- 2027 पर राज्यस्तरीय सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया

जयपुर, 7 फरवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सटीक जनगणना विकास योजनाओं का एक महत्वपूर्ण आधार है। जनगणना के समय संकलित आंकड़ों से ही केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का निर्धारण एवं क्रियान्वयन प्रभावशीलता के साथ संभव हो पाता है। इसलिए सभी कार्मिक जनगणना कार्य को राष्ट्रीय कर्तव्य मानकर पूरी निष्ठा से संपन्न करें।

शर्मा शनिवार को जनगणना-2027 पर वर्चुअली आयोजित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनगणना के पहले चरण, अर्थात् मकानों का सूचीकरण और मकानों की गणना का काम जितना सटीक होगा, व्यक्तियों की गणना का अगला चरण उतना ही त्रुटि रहित और सही होगा। उन्होंने कहा, आंकड़े सही नहीं होंगे तो न तो योजनाएं अच्छे से बन पाएंगी और न ही इनका क्रियान्वयन लक्ष्यों के अनुरूप हो पाएगा। शर्मा ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन भी जनगणना आंकड़ों के आधार पर होता है। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग करते हुए जनगणना कार्य किया जाएगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

■ **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आंकड़े सही नहीं होंगे तो, ना तो योजनाएं अच्छे से बन पाएंगी, और न ही उनका क्रियान्वयन लक्ष्यों के अनुरूप हो पाएगा।**

'क्या अनिल अंबानी ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पर अंबानी ने एपस्टीन को किसी यात्रा के दौरान एक महिला की व्यवस्था करने को लेकर लिखा था। पर्यवेक्षकों का कहना है कि इस तरह की भाषा एपस्टीन की उस चर्चित भूमिका से मेल खाती है, जिसमें वह शक्तिशाली लोगों के लिए एक सामाजिक फ़िक्सर के तौर पर काम करता था। हालाँकि इन दस्तावेज़ों में किसी भी तरह के आपराधिक कृत्य की पुष्टि नहीं होती, लेकिन भारत के कॉरपोरेट जगत में अनिल अंबानी की हैसियत और देश के राजनीतिक नेतृत्व से उनकी लंबे समय से मानी जाने वाली निकटता के कारण इन खुलासों की गहन जांच करने की आवश्यकता पैदा हो गई है। रिलायंस एडीए ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का करीबी माना जाता रहा है, यह रिश्ता मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के समय से है। यह संबंध 2016-17 में खास तौर पर चर्चा में आया, जब अंबानी समूह राफेल लड़ाकू विमान निर्माण परियोजना में एक प्रमुख भारतीय साझेदार के रूप में उभरा। यह सौदा लगभग 30,000 करोड़ रू. का था और फ्रांसीसी सरकार तथा डसॉल्ट एविएशन के सहयोग से किया गया था। राफेल सौदा पहले ही लंबे समय से राजनीतिक विवादों में घिरा रहा है। विपक्षी दलों ने ऑफ़सेट साझेदार के रूप में रिलायंस डिफेंस, जिसके पास एयरोस्पेस निर्माण का सीमित अनुभव था-के चयन पर सवाल उठाए थे। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में राफेल समझौते की न्यायालय-निगरानी में जांच के आदेश देने से इनकार कर दिया था, लेकिन आलोचकों का कहना है कि पारदर्शिता और उचित जांच से जुड़े कई अहम सवाल अब भी अनुत्तिरत हैं।

अब एपस्टीन दस्तावेज़ों में अंबानी के नाम के दोबारा सामने आने से राजनीतिक विरोधियों को नया हथियार मिल गया है। उनका तर्क है कि जिन व्यक्तियों की पहुंच संवेदनशील रक्षा परियोजनाओं तक है, उनसे सर्वोच्च स्तर की ईमानदारी और उनकी कड़ी जांच की अपेक्षा की जानी चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों और पूर्व नौकरशाहों का कहना है कि यह मुद्दा केवल व्यक्तिगत प्रतिष्ठा तक सीमित नहीं है। एपस्टीन के खुफिया एजेंसियों, वैश्विक अभिजात वर्ग और गंभीर आरोपों से जुड़े होने के इतिहास को देखते हुए विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसे किसी नेटवर्क से किसी भी प्रकार का, चाहे वह अप्रत्यक्ष ही क्यों न हो - संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित वैध सवाल खड़े करता है। एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, जब रक्षा निर्माण, रणनीतिक परिसंपत्तियाँ और विदेशी सरकारें शामिल हों, तो अप्रमाणित संबंध भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ प्रतिक्रियात्मक इनकार की बजाय सक्रिय पारदर्शिता की मांग करती हैं। विपक्षी नेताओं ने इस मामले पर संसद में चर्चा की मांग की है और ज़ोर दिया है कि सरकार स्पष्ट करे कि क्या भारतीय एजेंसियों को ऐसे अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जानकारी थी और क्या रणनीतिक रक्षा परियोजनाओं से जुड़े सभी हितधारकों की पर्याप्त पृष्ठभूमि जांच की गई थी।

फ़िलहाल अनिल अंबानी या प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से एपस्टीन फ़ाइलों में सामने आए संदर्भों पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं आई है। सरकारी सूत्रों ने निजी तौर पर इस विवाद को "राजनीतिक रूप से प्रेरित अटकलें" बताते हुए खारिज कर दिया है और इस बात पर ज़ोर दिया है कि किसी दस्तावेज़ में नाम आना दोष सिद्ध होने के बराबर नहीं है। कानूनी विशेषज्ञ भी इसी रुख की पुष्टि करते हैं और चेतावनी देते हैं कि निजी संवादों में उल्लेख को अवैध गतिविधि के प्रमाण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि, वे यह भी रेखांकित करते हैं कि राजनीतिक रूप से जुड़े व्यावसायिक व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक जवाबदेही के मानक स्वाभाविक रूप से अधिक कड़े होते हैं। यह प्रकरण एक बार फिर भारत में धन, सत्ता और शासन की सांठगांठ को उजागर करता है। यह देखना बाकी है कि यह विवाद किसी औपचारिक जांच की ओर बढ़ता है या पक्षपातपूर्ण राजनीति के शोर में दबकर रह जाता है। लेकिन फिलहाल, एपस्टीन से जुड़े खुलासों ने इस असहज सवाल को फिर से खोल दिया है कि भारत का राजनीतिक नेतृत्व और कॉरपोरेट अभिजात वर्ग कितनी गहराई से आपस में जुड़े हैं - और अंततः सार्वजनिक हित की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है।

■ **तो, क्या यह विवाद भी कालांतर में, आरोप-प्रत्यारोपों की बौछार की धुंध में दबकर लुप्त हो जाएगा या कभी सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि सच्चाई से देश की सुरक्षा जुड़ी है।**

अमेरिका ने अपने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भारत के आधिकारिक क्षेत्रीय नक्शे का इस्तेमाल एक बड़े आर्थिक साझेदारी के ऐलान के साथ करके अमेरिका ने व्यापार से आगे का संदेश दिया है। अमेरिका ने जम्मू-कश्मीर पर भारत के रुख के साथ खुद को जोड़ लिया है और इस मुद्दे को विवादित सवाल नहीं, बल्कि तय भौगोलिक सच्चाई के रूप में दिखाया है।

पाकिस्तान के लिए यह एक ऐसा झटका है, जो एक रुटीन डिप्लोमैटिक झटके से कहीं ज्यादा गंभीर है। इस्लामाबाद लंबे समय से कश्मीर मुद्दे को इंटरनैशनल लैवल पर जिंदा रखने के लिए बड़ी ताकतों, खासकर अमेरिका की अस्पष्ट नीति पर निर्भर रहा है। जबकि अमेरिका अक्सर दोनों पक्षों का खुलकर समर्थन करने से बचता रहा है और पहले भी विवादित क्षेत्रों को डैश वाली लाइनों या स्पष्टीकरण नोट के साथ दिखाता रहा है। यू.टी.एस.आर. के नक्शे में ऐसे चिन्हों का न होना इस नीति से अलग माना जा रहा है। ऐसा लगता है कि अमेरिका अपनी प्राथमिकताओं में बदलाव का संकेत दे रहा है। पाकिस्तान वॉशिंगटन के लिए टैक्टिकल इंटरैस्ट का हिस्सा बना हुआ है, चाहे वह सीमित काउन्टर टैररिज़्म को, ऑपरेशन के लिए हो, रीजनल स्टेबिलिटी की चिंताओं के लिए हो, या खास रिसोर्स तक पहुंचने के लिए हो। लेकिन उसे अब पहले जैसा रणनीतिक साझेदार नहीं माना जा रहा है। दूसरी तरफ भारत व्यापार, तकनीक, सप्लाई चेन और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन के मामले में अमेरिका की रणनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह प्राथमिकता अब नीति के साथ-साथ आधिकारिक तस्वीरों में भी दिखाई दे रही है। इसलिए वॉशिंगटन का संदेश कई परतों वाला, लेकिन साफ है। पाकिस्तान अभी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन दक्षिण एशिया में अमेरिकी नीति को तय करने वाला मुख्य देश अब भारत है। आधिकारिक व्यापार ग्राफिक में जम्मू-कश्मीर को भारत की सीमा के अंदर दिखाकर अमेरिका ने संकेत दिया है कि वह इस क्षेत्र को पुराने विवाद के बजाय, मौजूदा स्थिति के आधार पर देखता है।

■ **इस परिवर्तन से, जैसा कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया से जाहिर होता है, पाकिस्तान हिल गया है। क्योंकि, अब तक पाकिस्तान की विदेश नीति का आधार ही कश्मीर के विवाद को जारी रखना था, तथा हालांकि, अमेरिका ने कभी पाकिस्तान की कश्मीर नीति का खुलकर समर्थन नहीं किया था, पर, येन-केन-प्रकारेण कश्मीर विवाद को मरने भी नहीं दिया, सदा जीवित रखा।**

ट्रंप ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की भारी राजनीतिक कीमत पार्टी को चुकानी पड़ेगी। अश्वेत व हिस्पैनिक आदि मतदाताओं के एक बड़े वर्ग ने डॉनल्ड ट्रंप का समर्थन किया था और उन्हें वोट दिया था, लेकिन अब वे खुद को पूरी तरह ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस पोस्ट ने अमेरिकी समाज में नस्लवाद की गहराई और विस्तार को उजागर कर दिया है, और वह भी सर्वोच्च स्तर पर। कई अश्वेत मतदाता और यहां तक कि रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य भी अब उस दौर को याद कर रहे हैं, जब अमेरिका में अलगाव (सेग्रेगेशन) के दौर में भेदभाव और उत्पीड़न आम बात थी। उस दौर में अश्वेत समुदाय पर अत्याचार हुए और व्यापक स्तर पर भेदभाव किया गया। अमेरिकी टीवी चैनल अश्वेत और अन्य नागरिकों के साक्षात्कारों से भरे पड़े हैं, जहां लोग अपनी पीड़ा और आधिकारिक संस्थानों के प्रति अविश्वास व्यक्त कर रहे हैं। श्वेत वर्चस्ववादी वर्गों ने अक्सर अश्वेत समुदाय के सदस्यों के खिलाफ अपमानजनक और आक्रामक व्यवहार किया है। इसके बावजूद, डॉनल्ड ट्रंप को अश्वेत और हिस्पैनिक समुदाय के सदस्यों से काफ़ी समर्थन मिला था। अब इन समुदायों का बड़ा वर्ग इस घटनाक्रम से स्तब्ध है। यह घटना आगामी मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी के लिए भारी शर्मिंदगी और राजनीतिक नुकसान का कारण बन सकती है।

अमेरिका के साथ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तहत, बांग्लादेश चीन से आयात कम करने और अमेरिका से सैन्य ख़र्च बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताएगा। अमेरिका बांग्लादेशी बाज़ारों तक मुक्त पहुंच चाहता है और यह भी चाहता है कि अमेरिकी वाहन और उनके पुर्ज़े बिना निरीक्षण के आयात किए जाएँ।

अप्रैल 2025 में, ट्रंप प्रशासन ने बांग्लादेश पर 37 प्रतिशत टैरिफ लगाया था, जिसे बाद में घटाकर 35 प्रतिशत और अंततः 20 प्रतिशत कर दिया गया। इस नए समझौते के तहत, टैरिफ को और घटा कर 15 प्रतिशत तक किए जाने की उम्मीद है। यूनुस सरकार द्वारा अमेरिका के साथ जल्दबाज़ी में समझौता करने की एक बड़ी वजह भारत से जुड़ी है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था अमेरिका को होने वाले वस्त्र और रेडीमेड परिधान निर्यात पर काफ़ी हद तक निर्भर है, जो अमेरिका को उसके कुल निर्यात का लगभग 90 प्रतिशत है। बाँग्लादेश को आशंका है कि भारत-अमेरिका समझौते के औपचारिक रूप में आने के बाद, भारत उसका बाज़ार हिस्सा छीन सकता है। ढाका स्थित अख़बार "प्रथम आलो" के अनुसार, बांग्लादेश-अमेरिका समझौते पर 12 फ़रवरी को वॉशिंगटन में हस्ताक्षर किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के वाणिज्य सलाहकार एस.के. बशीरउद्दीन पहले ही इस समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, तथा अमेरिका में ट्रेड रिप्रेज़ेंटेटिव जैम्सन ग्रीर इस पर हस्ताक्षर करेंगे।

राहुल गांधी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा, बड़ी उम्र के किसी भी नेता को पुनः नामित किये जाने या सांसद के रूप में लाने की संभावना नहीं है। जहां कांग्रेस सामाजिक इंजीनियरिंग और जातीय समीकरण पर ध्यान केन्द्रित कर रही है, वहीं नेताओं का मानना है कि राज्यसभा में प्रतिभा के लिए कोटा होना चाहिए और व्यक्ति के पास विशेष ज्ञान या गहरी राजनीतिक समझ होनी चाहिए। वर्तमान व्यवस्था में यह पहलू गायब नज़र आता है।

टी-20 विश्व कप ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लिए एक बार फिर अपनी सरकार से सलाह करेगा। श्रीलंका ने पाक क्रिकेट बोर्ड से इस बारे में अनुरोध किया है।

पाकिस्तान सरकार ने पीसीबी को टी20 विश्व कप के लिए राष्ट्रीय टीम भेजने की अनुमति तो दे दी है, लेकिन भारत के खिलाफ खेलने से इसे रोक दिया है। ज्ञातव्य है कि भारत-पाकिस्तान मुकाबला आईसीसी और उसके प्रसारकों के लिए व्यावसायिक रूप से सबसे बड़ा मैच माना जाता है।

इस वजह से श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) ने पीसीबी को एक ईमेल भेजा है, जिसमें कहा गया है कि 15 फ़रवरी को चिर-प्रतिद्वंद्वियों के बीच होने वाला यह हाई-प्रोफाइल मैच नहीं होने से एसएलसी को आर्थिक नुकसान होगा और भारत के साथ संयुक्त रूप से टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहे इस द्वीपीय देश (श्रीलंका) में प्रतियोगिता की छवि और आयोजन को भी ठेस पहुंचेगी।

भाजपा की रितु ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

15 जनवरी को हुए नगर निकाय चुनाव में वार्ड नंबर 5 से चुने गए शिवसेना के संजय शंकर घाड़ी उप-महापौर होंगे। वे 15 महीने तक इस पद पर रहेंगे। शिवसेना उप-महापौर का कार्यकाल अपने चार पार्षदों में बाँटेगी।

भाजपा नेता अमित सातम ने ऋतु तावड़े के नाम की घोषणा की, जबकि शिवसेना नेता राहुल शेवाले ने शनिवार को संजय घाड़ी की उम्मीदवारी का ऐलान किया। ये अति महत्वपूर्ण चुनाव नौ साल के अंतराल के बाद हुए। इस दौरान 7 मार्च 2022 से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक नगर निकाय प्रमुख के रूप में कार्यरत था, क्योंकि नगर निकाय का पिछला कार्यकाल समाप्त हो गया था।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालयः एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908